

प्रेषक,

डी० पी० गैरोला,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक : 22 दिसम्बर, 2011

विषय: मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को
दिनांक 01-04-2009 से विशेष भत्ता स्वीकृत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 4808/UHC/III/3/2009-10 दिनांक 14-10-2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है श्री राज्यपाल वेतन विसंगति समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 311/XXVII (7)40(15)/2011 दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 में उल्लिखित विवरणानुसार मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में कार्यरत अनुभाग अधिकारी/समकक्ष अधिकारियों से उच्च पदधारको को, न्यायिक सेवा के अधिकारियों को छोड़ते हुए, शासनादेश संख्या-80/XXXVI(1)/2011-135/2007 दिनांक 25 जुलाई 2011 के आधार पर दिनांक 01-01-2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमानों में सुसंगत ग्रेड वेतन का 20 प्रतिशत की दर से विशेष भत्ता दिनांक 01-04-2009 से अनुमन्य कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त भत्ता स्वीकृति के फलस्वरूप दिनांक 01-04-2009 से 30-11-2011 तक के एरियर की समस्त धनराशि सम्बन्धित कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी और जो कर्मचारी उक्त निधि के सदस्य नहीं है, उन्हें उक्त एरियर का भुगतान राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से किया जायेगा। जो कर्मचारी इस बीच सेवानिवृत्त हो चुके हैं या सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें एरियर की धनराशि का नकद भुगतान किया जायेगा।

3- वर्तमान में मा० उच्च न्यायालय में कम्प्यूटर पर कार्य किया जा रहा है। फलस्वरूप इस आधार पर टाईपराइटर मैकनिक के पद को बनाये रखे जाने का औचित्य नहीं है। अतः उक्त पद पर कार्यरत पदधारक को भी उक्तानुसार विशेष भत्ता इस शर्त पर अनुमन्य होगा कि उक्त पद डाईंग कैडर माना जायेगा।

4- विशेष भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में अन्य शर्तें यथावत लागू रहेगी।

5- उक्त सम्बन्ध में होना वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक" 2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-102-उच्च न्यायालय-03-उच्च न्यायालय के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

Munna

(2)

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-194/XXVII(7)/2011 दिनांक 22-12-2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी० पी० गैरोला)
प्रमुख सचिव

संख्या- 204 /XXXVI(1)/2011-135/2007 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून
- 2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 3- वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7
- 4- गार्ड फाईल/एन०आई०सी०।

आज्ञा से,

(एम० एम० सेमवाल)
उपसचिव